

## ‘ई.वी. एक सेवा के रूप में’ कार्यक्रम

**सन्दर्भ:** हाल ही में कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) ने ‘ईवी एज अ सर्विस’ कार्यक्रम की शुरुआत की है, जोकि सरकारी मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में अगले दो वर्षों में 5,000 इलेक्ट्रिक कारों तैनात करने का लक्ष्य रखता है। यह पहल भारत में हरित मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

### कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं:

ईवी एज ए सर्विस कार्यक्रम, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के इच्छुक सरकारी विभागों के लिए कई लाभ प्रदान करता है:

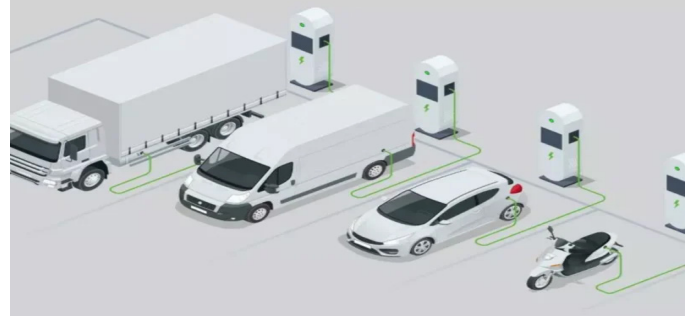
- **लचीला क्रय मॉडल:** यह कार्यक्रम सरकारी विभागों को उनकी परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न इलेक्ट्रिक वाहन मॉडलों का चयन करने की सुविधा प्रदान करता है। यह लचीलापन सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की स्थापना प्रत्येक विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं, बेड़े के आकार और उपयोग पैटर्न के साथ सटीकता से मेल खाए।
- **सरकारी कार्यालयों में ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देना:** यह पहल 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।
- **ऊर्जा सुरक्षा को समर्थन:** इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से भारत की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी और ऊर्जा दक्षता के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।
- **हितधारक सहयोग:** यह पहल निर्माताओं, बेड़ा संचालकों, नीति निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं को एक सहयोगात्मक पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल कर टिकाऊ गतिशीलता समाधानों को बढ़ावा देती है। यह प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के अनुरूप है, जो भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित करती है।
- **प्रगति एवं उपलब्धियां:** CESL ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में पहले भी महत्वपूर्ण प्रगति की है और देश में लगभग 2,000 इलेक्ट्रिक कारें तैनात की हैं। इसके अतिरिक्त, संगठन ने लगभग 17,000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती को भी प्रोत्साहित किया है।

### CESL के बारे में:

- कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL), एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) की एक सहायक कंपनी है और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन काम करती है। CESL का उद्देश्य भारत में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा-कुशल समाधानों को बढ़ावा देना है।

### इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्या हैं ?

- इलेक्ट्रिक वाहन विद्युत मोटरों का उपयोग करते हैं और पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (ICE) को प्रतिस्थापित करते हैं।



### इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रकार:

- **बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV):** केवल बैटरी पावर पर चलते हैं और शून्य टेलपाइप उत्सर्जन करते हैं।
  - **प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (PHEV):** इलेक्ट्रिक मोटर और गैसोलीन इंजन का संयोजन होता है और बाहरी रूप से चार्ज किया जा सकता है।
  - **हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (HEV):** इनमें इलेक्ट्रिक मोटर और गैसोलीन इंजन का संयोजन होता है लेकिन बैटरी को सीधे चार्ज नहीं किया जा सकता।
- ### इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ:
- **उत्सर्जन में कमी:** इलेक्ट्रिक वाहन शून्य टेलपाइप उत्सर्जन करते हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है।
  - **कम परिचालन लागत:** इन वाहनों का संचालन गैसोलीन की तुलना में सस्ता हो सकता है क्योंकि बिजली की लागत कम होती है।
  - **‘शोर में कमी’:** विद्युत मोटर कम शोर उत्पन्न करते हैं।
  - **बेहतर दक्षता:** विद्युत मोटर ऊर्जा को अधिक उपयोगी शक्ति में परिवर्तित करती है।

## कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की रिपोर्ट में साइबर सुरक्षा के बढ़ते खतरों का खुलासा

**सन्दर्भ:** हाल ही में जारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट भारत में साइबर सुरक्षा की स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त करती है, विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिमों के संदर्भ में।

- रिपोर्ट में साइबर अपराध की घटनाओं में तेजी से वृद्धि को उजागर किया गया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - » रक्षा इकाई पर रैनसमवेयर हमला
  - » लाखों भारतीय नागरिकों को प्रभावित करने वाला एक विशाल



#### डेटा उल्लंघन

- » महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए गए दुर्भावनापूर्ण साइबर हमले

### डीओपीटी (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- **रक्षा इकाई पर रैनसमवेयर हमला:** 2023 में, एक रक्षा इकाई रैनसमवेयर हमले की चपेट में आ गई। रैनसमवेयर डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है और उसे अनलॉक करने के लिए फिरौती की मांग करता है। इस हमले ने महत्वपूर्ण कंप्यूटर प्रणालियों तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया, जिससे भारत के रक्षा बुनियादी ढांचे की बढ़ती भेद्यता उजागर हुई।
- **डेटा उल्लंघन से 81 करोड़ भारतीय प्रभावित:** भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को बड़ी डेटा चोरी का सामना करना पड़ा। इस उल्लंघन का पता अक्टूबर 2023 में अमेरिका स्थित साइबर सुरक्षा फर्म रीसिक्वोरिटी को चला। इस उल्लंघन ने भारत के डेटा संरक्षण तंत्र की गंभीर खामियों को उजागर किया, जिससे नागरिकों की गोपनीयता और पहचान की चोरी का खतरा पैदा हो सकता है।
- **मंत्रालय पर मैलवेयर हमला:** 2023 में एक मैलवेयर हमले ने एक सरकारी मंत्रालय को निशाना बनाया।
- **मैलवेयर का प्रभाव:** मैलवेयर हमले महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे वर्गीकृत जानकारी की चोरी या आवश्यक सेवाओं में व्यवधान। इससे सरकारी प्रणालियों में अधिक सतर्कता और सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता रेखांकित होती है।
- **महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर DDOS हमले:** डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल-ऑफ-सर्विस (DDOS) हमले ने भारत के हवाई अड्डों सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया।

### डीडीओएस कैसे काम करता है:

- डीडीओएस हमले सर्वरों पर अत्यधिक ट्रैफिक ला देते हैं, जिससे वे निष्क्रिय हो जाते हैं और सेवा में बाधा उत्पन्न होती है।

### साइबर सुरक्षा घटनाओं में वृद्धि:

- CERT-In (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम) ने साइबर सुरक्षा घटनाओं में वृद्धि की सूचना दी:
- 2023 में 15,92,917 घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि 2017 में यह संख्या केवल 53,117 थी। इन घटनाओं में कई प्रकार की धमकियां शामिल थीं। जैसे:
  - » वेबसाइट घुसपैठ
  - » मैलवेयर प्रसार
  - » फिशिंग हमले
  - » डीडीओएस हमले
  - » अनधिकृत नेटवर्क गतिविधियाँ



### धोखाधड़ी के प्रकार:

- **क्रिप्टो धोखाधड़ी:** एक फर्जी तकनीकी सहायता कॉल सेंटर से जुड़े 2 मिलियन डॉलर के क्रिप्टोकॉर्सेसी घोटाले का पर्दाफाश किया गया। सीबीआई ने भारत में बड़े पैमाने पर क्रिप्टो माइनिंग घोटाले का भी पर्दाफाश किया, जहां अपराधियों ने नागरिकों को फर्जी क्रिप्टो माइनिंग परिचालन में 100 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए गुमराह किया।
- **कॉल सेंटर धोखाधड़ी:** सीबीआई ने भारत में संचालित कई कॉल सेंटर धोखाधड़ी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया, जोकि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के नागरिकों को निशाना बनाते थे।
- **निवेश और ऋण ऐप धोखाधड़ी:** सीबीआई ने निवेश और ऋण ऐप धोखाधड़ी की भी जांच की, जहां धोखाधड़ी के जरिए नागरिकों, विशेष रूप से पड़ोसी देशों के नागरिकों को निशाना बनाया गया। ये ऐप्स निवेशकों को फंसाने के लिए भ्रामक रणनीति का इस्तेमाल करते थे।

### साइबर सुरक्षा समन्वय का बदलता परिदृश्य:

- सितंबर 2023 में, कैबिनेट सचिवालय ने व्यवसाय आवंटन नियमों में संशोधन किया और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA), अजीत डोभाल के अधीन रखा। डोभाल को साइबर सुरक्षा पर रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा की देखरेख के लिए नामित किया गया, जबकि गृह मंत्रालय (MHA) को साइबर अपराधों से निपटने की जिम्मेदारी दी गई।

### वैश्विक कार्बन बाजार और जलवायु वित्त

**सन्दर्भ:** हाल ही में बाकू, अजरबैजान में आयोजित COP29 शिखर सम्मेलन ने वैश्विक कार्बन बाजार के विकास और जलवायु वित्त लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की। इस सम्मेलन में पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 को अंतिम रूप देने और जलवायु वित्त के लिए नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्यों (NCQG) को स्थापित करने पर चर्चा की गई।

### वैश्विक कार्बन बाजार के लिए रूपरेखा:



14 November 2024

- **अनुच्छेद 6.2:** यह कार्बन क्रेडिट के द्विपक्षीय व्यापार की अनुमति देता है, जिससे देशों को उत्सर्जन में कमी लाने के लिए आपसी सहयोग का अवसर मिलता है।
- **अनुच्छेद 6.4:** यह संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में वैश्विक कार्बन बाजार की स्थापना करता है, जिससे द्विपक्षीय समझौतों से परे व्यापक और विनियमित व्यापार संभव हो पाता है।
- **कार्बन क्रेडिट:** यह उत्सर्जन में प्रमाणित कटौती का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो टिकाऊ परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देते हैं और देशों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) हासिल करने में मदद करते हैं।

### COP29 में प्राप्त प्रगति:

- राष्ट्रों ने कार्बन निष्कासन की सत्यापन प्रक्रिया के लिए नए मानकों को मंजूरी दी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्रेडिट प्रामाणिक और विश्वसनीय हों।
- COP29 के अध्यक्ष, मुख्तार बाबायेव, ने कहा कि अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन से जलवायु लक्ष्यों की लागत में प्रतिवर्ष 250 बिलियन डॉलर की कमी आ सकती है।
- इन प्रगतियों से यह उम्मीद जताई जा रही है कि कार्बन ट्रेडिंग विकासशील देशों की ओर संसाधन लाने के लिए एक "खेल-परिवर्तनकारी उपकरण" बन सकती है।

### कार्बन बाजार में चुनौतियाँ:

- दुरुपयोग से बचने और वास्तविक उत्सर्जन में कमी सुनिश्चित करने के लिए क्रेडिट सत्यापन में पारदर्शिता और जवाबदेही महत्वपूर्ण है।
- स्पष्ट दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है कि ऋण कब व्यापार योग्य होंगे और ऋण का स्वामित्व किसके पास रहेगा।
- इन मानकों की व्यापक स्वीकृति सुनिश्चित करना सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों के लिए एक प्राथमिकता बनी हुई है।

### स्वामित्व और पात्रता संबंधी मुद्दे:

- **ऋण स्वामित्व:** यदि कोई विकसित देश किसी विकासशील देश में कार्बन कम करने वाली परियोजना को वित्तपोषित करता है, तो यह सवाल उठता है कि उत्सर्जन में कमी का दावा कौन कर सकता है।
- **पात्रता मानदंड:** किसी परियोजना के जीवनचक्र के किस चरण पर क्रेडिट व्यापार के लिए पात्र हो जाएगा, इसका निर्धारण सटीक लेखांकन के लिए आवश्यक है।
- **एनडीसी रिपोर्टिंग:** देशों को यह स्पष्ट करना होगा कि क्या उनकी सीमाओं के भीतर विदेशी वित्तपोषित परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न ऋणों को उनके एनडीसी लक्ष्यों में गिना जा सकता है या नहीं।

### भारत की प्रतिबद्धताएँ और आवश्यकताएँ:

- भारत का लक्ष्य 2005 के स्तर से उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम

करना और 2030 तक 2.5-3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना है।

- एक प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत को अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए स्पष्ट ऋण स्वामित्व नियमों की आवश्यकता है।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण और कार्बन क्रेडिट स्वामित्व के प्रबंधन में पारदर्शी नियमों के महत्व को रेखांकित करता है।



### जलवायु वित्त के लिए नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसीक्यूजी):

- विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने के लिए विकसित देशों के लिए निर्धारित प्रारंभिक 100 बिलियन डॉलर के वार्षिक जलवायु वित्त पोषण लक्ष्य को अद्यतन किया गया है।
- एनसीक्यूजी का उद्देश्य जलवायु अनुकूलन और शमन प्रयासों की बढ़ती लागत को संबोधित करते हुए इस लक्ष्य को बढ़ाना है।
- एनसीक्यूजी के 2025 तक प्रभावी होने की उम्मीद है और यह कमजोर क्षेत्रों की मदद करने के लिए विकसित देशों की वित्तीय जिम्मेदारी को रेखांकित करता है।
- एनसीक्यूजी वैश्विक स्तर पर महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार तैयार कर सकता है।

### निष्कर्ष:

बाकू में आयोजित COP29 ने वैश्विक कार्बन बाजार और जलवायु वित्त ढाँचों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कार्बन क्रेडिट की प्रामाणिकता के लिए मानक तय किए गए और एनसीक्यूजी में भी सुधार हुआ। COP29 ने जलवायु कार्रवाई के लिए सहकारी दृष्टिकोण पर जोर दिया है। इन ढाँचों का 2025 तक कार्यान्वयन होने की उम्मीद है, फिर यह कार्बन बाजार और जलवायु वित्त वैश्विक जलवायु लक्ष्यों और सतत विकास के लिए आवश्यक उपकरण बन जाएंगे।

Face to Face Centres





## पावर पैकड न्यूज

### तैयब इकराम पुन: अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए

- ओमान के मस्कट में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) वैधानिक सम्मेलन में तैयब इकराम को चार वर्ष के पूर्ण कार्यकाल के लिए पुनः अध्यक्ष चुना गया।
- पाकिस्तान में जन्मे इकराम, जिन्होंने पहले दो साल का कार्यकाल पूरा किया था, ने पूर्व अध्यक्ष नरिंदर सिंह बत्रा के इस्तीफे के बाद 2022 में यह भूमिका संभाली थी। उनका पुनः निर्वाचन एफआईएच के नेतृत्व में स्थिरता और निरंतरता का संकेत है, जोकि वैश्विक हॉकी प्रशासन में निरंतर प्रगति की भावना को बढ़ावा देता है।
- इकराम का निरंतर नेतृत्व एफआईएच के मिशन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य इनडोर और फील्ड हॉकी के विकास को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है।
- इकराम के साथ दाने एंडाडा (यूआरयू), अल्बर्टो डैनियल बुडस्की (एआरजी), और एरिक कॉर्नेलिसन (एनईडी) को भी एफआईएच कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में पुनः चुना गया। साथ ही, कैटरिन कौशके (जर्मनी) भी बोर्ड में शामिल हो रहे हैं।
- स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित एफआईएच, फील्ड हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय विकास, नियमों और टूर्नामेंट के आयोजन की देखरेख करता है। इकराम के नेतृत्व से खेल की वैश्विक पहुंच को और बढ़ाने और सदस्य देशों में समावेशिता तथा विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

### 2024 ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर

- हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार, दुबई मध्य पूर्व और अफ्रीका में शीर्ष स्थान पर है और अब यह विश्व स्तर पर 5वां सबसे प्रभावशाली शहर बन गया है।
- दुबई ने सिंगापुर, लॉस एंजिल्स और सिडनी जैसे प्रमुख शहरों को पीछे छोड़ते हुए यह स्थान प्राप्त किया है, जबकि लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क शीर्ष तीन स्थानों पर बने हुए हैं।
- दुबई के उत्थान का एक प्रमुख कारण स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कार्य के अवसरों में सुधार पर इसका ध्यान केंद्रित करना है, जिससे यह काम की सुलभता में 24वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गया है। शहर के मजबूत बुनियादी ढांचे, रणनीतिक व्यापार साझेदारी और आर्थिक स्थिरता ने इसके 100 में से 86 के उच्च समग्र स्कोर में योगदान किया है।
- व्यापार, वित्त और पर्यटन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में, दुबई ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए अपने रणनीतिक स्थान का लाभ उठाया है। आर्थिक नीतियों के प्रति दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ, दुबई एक अग्रणी वैश्विक शहर के रूप में विकसित हो रहा है।



Dubai ranks highest in Middle East and North Africa in '2024 Global City Index'

### यूरेशियन ऊदबिलाव

- पुणे जिले के इंदापुर में एक दुर्लभ यूरेशियन ऊदबिलाव (लूट्रा लूट्रा) को बचाया गया, जोकि इस क्षेत्र में इस प्रजाति का रिकॉर्ड किया गया पहला दृश्य है। यह बचाव अभियान पुणे वन विभाग और आरईएसक्यू चौरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया, जब उन्हें एक कुएं में फंसे सिवेट के बारे में सूचना प्राप्त हुई।
- वन रक्षकों और आरईएसक्यू टीम के सदस्यों ने ऊदबिलाव को सुरक्षित निकालने के लिए ऑटो-ट्रैप पिंजरे का उपयोग करते हुए छह घंटे का ऑपरेशन किया। इसके बाद उसे मूल्यांकन के लिए पुणे स्थित वन्यजीव ट्रांजिट उपचार केंद्र भेजा गया।
- यह अप्रत्याशित दृश्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरेशियन ऊदबिलाव सामान्यतः यूरोप, हिमालय की तलहटी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ये ऊदबिलाव स्वच्छ, मीठे पानी के वातावरण में रहते हैं और मछलियों से भरपूर होते हैं। वे एकांतप्रिय, रात्रिचर और प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं।



### Face to Face Centres



14 November 2024

- यूरेशियन ऊदबिलाव को IUCN द्वारा 'निकट-संकटग्रस्त' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (अनुसूची II) के तहत संरक्षित हैं और CITES के परिशिष्ट I में सूचीबद्ध हैं, जो इनके संरक्षण के महत्व को दर्शाता है।

## अजरबैजान

- अजरबैजान, जोकि यूरेशिया के दक्षिण काकेशस क्षेत्र में स्थित है, एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला एक अंतरमहाद्वीपीय राष्ट्र है। इसकी राजधानी बाकू ने हाल ही में 2024 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी सीओपी 29) की मेजबानी की। अजरबैजान की सीमा उत्तर में रूस, उत्तर-पश्चिम में जॉर्जिया, पश्चिम में आर्मेनिया, दक्षिण में ईरान और पूर्व में कैस्पियन सागर से लगती है।

### राजनीतिक और भौगोलिक विशेषताएँ:

- भूमि सीमाएँ:** अजरबैजान की भूमि सीमाएँ रूस, ईरान, आर्मेनिया और जॉर्जिया से लगती हैं।
- जल निकाय:** कैस्पियन सागर इसके पूर्व में स्थित है, जो अजरबैजान के व्यापार और प्राकृतिक संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है।
- प्रमुख नदियाँ:** कुरा और अरास नदियाँ अजरबैजान की सिंचाई और कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- उच्चतम शिखर:** बजारद्युज्यू, जो ग्रेटर काकेशस पर्वतमाला का हिस्सा है, अजरबैजान का सबसे ऊँचा शिखर है।
- क्षेत्रीय विवाद:** अजरबैजान का नागोर्नो-करबाख क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा है।
- प्राकृतिक संसाधन:** अजरबैजान प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, विशेष रूप से तेल और प्राकृतिक गैस, साथ ही सीसा, जस्ता, लोहा और तांबा जैसे खनिजों के मामले में। ये संसाधन अजरबैजान की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- अजरबैजान की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और संसाधनों की प्रचुरता, इसके क्षेत्रीय प्रभाव और भू-राजनीतिक महत्व को निर्णायक रूप से मजबूत बनाती है।



## Face to Face Centres

